employment and income generating programmes and asset-building for the poor. The main among these programmes are the Integrated Rural Development Programme, Jawahar Rozgar Yojana, Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister Rozgar Yojana for the Educated Unemployed Youth. In this connection a Basic Minimum Services Programme was launched last year for which Rs. 2244 crores were provided by Government of India in 1996-97 and Rs. 2970 crores have been provided in Annual Plan of 1997-98. Government have also implemented a national Employment Assurance Scheme.

गरीबी की रेखा से नीचे और उससे ऊपर जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों का वर्गीकरण

1398. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है और देश में उनकी आबादी का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर के ऐसे व्यक्तियों, जो जीवन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या देश के संतुलित विकास के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पहचान करना आवश्यक है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) जी, हां। योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीब तथा अन्य लोगों की संख्या के अनुमान न्यूनतम आवश्यकताओं तथा प्रभावकारी उपभोग मांग के अनुमानों पर कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर तैयार करता है। गरीबों की संख्या के अनुपात के अनुमान पर योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने उसके अनुमान लगाने हेतु एक वैकल्पिक पद्धति प्रस्तुत की है।

(ख) गरीबी के अनुमान, घरेलू उपभोक्ता व्यय पर पंचवर्षीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या के अभी हाल ही के अनुमान 1993-94 में किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण (एन एस एस 50 वां दौर) पर आधारित हैं। 1993-94 में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या कार्यबल विधि द्वारा 149.8 मिलियन तथा विशेषज्ञ दल विधि द्वारा 323.4 मिलियन अनुमानित की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गरीबी की समस्या के आकलन और गरीबी कम करने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु गरीबों की पहचान करना आवश्यक है।

Guideline for Private Investment in Power Sector

1399. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines to attract private investment in power projects, transmission and operational parameters etc.;

(b) whether despite various liberalization measures not many investors have come forward so far to participate in the power generation programme;

(c) whether foreign investors have been more discouraged due to conditions prevailing in almost all the Electricity Boards;

(d) the details of each State where such projects have been initiated with foreign investment alongwith the names of investors and countries which they belong to;

(e) whether Government are likely to further liberalize the power policy; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (f) The response of the private sector to the private power programme of Government of India has been encouraging with 128 expressions of interest for setting up power projects in the private sectors. These include 56 proposals from foreign investors, details of which are given in Annexure [*See Appendix. 180, Annexure No. 34]*. The power policy is amended from time to time, keeping in view the changing requirements.

Electricity Regulatory Commissions in the Centre and States

1400. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI MD. SALIM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under the Common Minimum National Action Plan for power to set up State level independent State Electricity Regulatory Commissions (SERC);

(b) if so, whether Government proposed to set up an independent Central Electricity Regulctory Commission (CERC) also; if not the reasons therefor;

(c) whether appeals against orders of SERC will lie before the respective State High Courts or before the proposed CERC; and

(d) whether appeals against orders of CERC will lie before the Supreme Court; if not the reasons therefor and the methodology proposed to resolve disputes between central utilities and the state agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes. Sir.

(b) to (d) The proposals in this regard are under consideration of Government.

नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम (एन० जे० पी० सी०) के अधिकारी

1401. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 1995 से 31 दिसम्बर, 1996 तक नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम के कौन-कौन से अधिकारी कितने-कितने दिनों तक दिल्ली और शिमला स्थित कार्यालयों में रहे तथा उन्होंने कितना-कितना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लिया;

(ख) दिल्ली के भाई वीर सिंह मार्ग स्थित नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम की कार्यालय में काम कर रहे 36 व्यक्ति किन-किन पदों पर हैं और शिमला स्थित कार्यालय में कितने अधिकारी किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं;

(ग) नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम के उपर्युक्त दोनों कार्यालयों द्वारा प्रतिमाह अलग-अलग कितना-कितना किराया दिया जा रहा है, और

(घ) क्या नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय की 7727 वर्ग फुट भूमि वापस करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसमें कितना समय लगेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) 1.11.95 से 31.12.96 के दौरान दिल्ली में नाथपा झाकडी विद्युत निगम (एनजेपीसी) के अधिकारियों द्वारा बिताए गए दिनों की संख्या के विवरण में दर्शाया गया है (**नीचे देखिए**)। इसी अवधि के दौरान दिल्ली में उनके रहने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु एनजेपीसी द्वारा लगभग 4.21 लाख रुपए का व्यय किया गया।